

विश्वनाथ समाचार

‘जनता की सोच — जनहित की खोज’

vishwanathsamachar@gmail.com

वर्ष 01 अंक :- 10

इंदौर, मंगलवार 15 सितम्बर से 14 अक्टूबर 2026 तक

पृष्ठ 8, मूल्य 5 रुपया

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रज्ज्वलित विकास के दीपक का प्रकाश फैल रहा है देशभर में : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

बेहतर समन्वय और अधिक से अधिक जनसहभागिता की जाये सुनिश्चित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रज्ज्वलित विकास के दीपक का प्रकाश देशभर में फैल रहा है। यह श्री मोदी के सेवा और जिम्मेदारी के 25 वर्षों के उजास का प्रतीक है। प्रदेश में सेवा-संकल्प अभियान 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक संचालित होगा। प्रदेशवासी प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर को बड़ी संख्या में दीप प्रज्ज्वलित कर उनके प्रति आभार प्रदर्शित करेंगे, हमारा प्रयास हो कि इस अवसर पर दीप प्रज्ज्वलन का विश्व रिकॉर्ड कायम हो। सेवा संकल्प अभियान का आयोजन ग्राम और नगर स्तर पर अधिक से अधिक जनसहभागिता



सुनिश्चित करते हुए उत्साह पूर्वक किया जाये। सभी कार्यक्रमों की पूर्ण तैयारी के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर

प्रभावी मॉनीटरिंग हो। विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी बेहतर

समन्वय और सभी संबंधितों की शत-प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सेवा के रंग-राष्ट्र के संग

कार्यक्रम के अंतर्गत जबलपुर में ह्यूमन रंगोली का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश में जारी तैयारियों की समत्व भवन में समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, मंत्री श्री राकेश सिंह, मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, मंत्री श्री विश्वास सारंग, श्री नागर सिंह चौहान, मंत्री श्री राकेश शुक्ला, मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार और राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल वरुचुअली शामिल हुए। समत्व भवन में हुई बैठक में मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव

श्री नीरज मंडलोई, श्री केसी गुप्ता, श्री संजय दुबे, श्री अनुपम राजन, श्री संजय शुक्ला, श्री शिवशेखर शुक्ला तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक से समस्त संभागयुक्त तथा जिला कलेक्टर वरुचुअली जुड़े। सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर को आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में दीप प्रज्ज्वलन के साथ होगी। उज्जैन के महाकाल महालोक सहित प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में शाम 7 बजे एकसाथ दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, उज्जैन के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे।

मैं
अनुराधा पौडवाल
आ रही हूँ
देपालपुर

17 अक्टूबर | देवी मंदिर, देपालपुर (इंदौर)

चिट्टू वर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा इन्दौर

बांग्लादेश बोला- भारत से नए सिरे से रिश्ते बनाएंगे



ढाका। बांग्लादेश ने रविवार को कहा कि वह भारत के साथ अपने रिश्ते को रीसेट करना चाहता है। यानी दोनों देशों के बीच संबंधों को नए सिरे से शुरू करना चाहता है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूँ कबीर ने कहा कि दोनों देशों के बीच नया रिश्ता आपसी हितों के आधार पर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहने के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंधों को असहज बताया। कबीर ने कहा कि ढाका नई दिल्ली के साथ नए रिश्ते की ओर बढ़ना चाहता है और इसके लिए दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत होनी चाहिए। यह बातचीत किसी बहुपक्षीय मंच के जरिए नहीं, बल्कि द्विपक्षीय स्तर पर होनी चाहिए। कबीर ने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ रिश्तों को लेकर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की सोच से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंधों को संतुलित तरीके से देखना चाहिए और आपसी हितों पर ध्यान देना चाहिए। नई दिल्ली के साथ रिश्ता बांग्लादेश के दूसरे देशों के साथ संबंधों का भी एक हिस्सा है। बांग्लादेश का यह बयान भारत में हुए ब्रिक्स समिट के खत्म होने के आया है। बांग्लादेश ने कहा था कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से न्योता नहीं दिया गया था। ढाका के मुताबिक, उन्हें के अध्यक्ष के तौर पर आमंत्रित किया गया था। बंगाल की खाड़ी से जुड़े दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के 7 देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जो आपसी सहयोग और विकास के लिए मिलकर काम करता है। ब्रिक्स से पहले भारत ने दोनों देशों के बीच एक अलग द्विपक्षीय मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री तारिक को निमंत्रण दिया था। उन्हें 22 अगस्त को भारत आना था, लेकिन दौरे से पहले ही यह कार्यक्रम टल गया था। उस समय बांग्लादेश ने भारत के सामने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया था। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर पहले से तनाव चल रहा है। इस पर बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूँ कबीर ने उस वक्त कहा था कि, जब माहौल सही होगा, तब द्विपक्षीय दौरे होंगे।

धामनोद में घर से 56 किलो गांजा बरामद, पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

नारकोटिक्स सेल इंदौर की कार्रवाई ने खोली स्थानीय पुलिस की सतर्कता की पोल, टीआई संतोष यादव और सीआई सेल रविराज सोलंकी की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

विश्वनाथ समाचार

धामनोद। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे 'नशे पर प्रहार' अभियान के तहत नारकोटिक्स सेल इंदौर ने धामनोद थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान से 56 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाई में ग्राम सुन्देल सगड़ीपुरा के कहार मोहल्ला निवासी 49 वर्षीय विक्रम चटर्जी पिता छोगालाल चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स सेल की इस कार्रवाई ने जहां नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को सामने रखा है, वहीं दूसरी ओर धामनोद थाना पुलिस और सीआई सेल की स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

थाना क्षेत्र में इतना बड़ा स्टॉक, स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस थाना क्षेत्र में किसी मकान से 56 किलो से अधिक गांजा बरामद होता है, वहां लंबे समय से संचालित हो रही इस गतिविधि की जानकारी स्थानीय पुलिस के मुखबिर तंत्र और निगरानी व्यवस्था को क्यों नहीं लगी? यदि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ किसी मकान में रखा हुआ था तो यह महज एक व्यक्ति द्वारा की जा रही छोटी-मोटी गतिविधि का मामला नहीं माना जा सकता। इतनी मात्रा में मादक पदार्थ की उपलब्धता अपने आप में सप्लाई नेटवर्क, संपर्कों और स्थानीय स्तर पर गतिविधियों की अवधि को लेकर जांच की जरूरत पैदा करती है। ऐसे में धामनोद थाना प्रभारी संतोष यादव तथा सीआई सेल प्रभारी रविराज सोलंकी की भूमिका सीधे तौर पर जांच का विषय तो नहीं कही जा सकती, लेकिन उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिलने के बाद उनकी निगरानी और सूचना तंत्र की कार्यक्षमता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।



नारकोटिक्स सेल ने पहुंचकर पकड़ लिया, स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी?

इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कार्रवाई नारकोटिक्स सेल इंदौर द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर की गई। इससे यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि क्या स्थानीय पुलिस के पास इस गतिविधि को लेकर कोई सूचना नहीं थी या फिर सूचना होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी? अगर स्थानीय स्तर पर पुलिस का मुखबिर तंत्र सक्रिय था तो 56 किलो 150 ग्राम गांजा आखिर स्थानीय पुलिस की नजर से कैसे बचा रहा? और यदि स्थानीय पुलिस को इसकी

जानकारी नहीं थी तो फिर थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की निगरानी और सूचना संकलन की व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इसका जवाब भी वरिष्ठ अधिकारियों को तलाशना होगा।

संरक्षण की बात सामने आई तो जांच जरूरी

इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने के बाद क्षेत्र में यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या आरोपी लंबे समय से इस गतिविधि में संलिप्त था? क्या उसके संपर्कों और पूरे नेटवर्क की जांच की जाएगी? क्या स्थानीय स्तर पर उसे किसी प्रकार का सहयोग या संरक्षण मिला था? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल उपलब्ध कार्रवाई में स्थानीय थाना पुलिस अथवा सीआई सेल की संलिप्तता या संरक्षण की कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस विभाग के लिए यह जरूर गंभीर विषय है कि उसके अधिकार क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ मौजूद रहा और इसकी जानकारी स्थानीय तंत्र को नहीं हो सकी।

वरिष्ठ अधिकारी कराएं निष्पक्ष समीक्षा

नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई के बाद अब आवश्यकता है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी केवल गांजा बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी तक मामला सीमित न रखें, बल्कि यह भी पता लगाएं कि-

- आरोपी के पास 56 किलो 150 ग्राम गांजा कब से था?
 - गांजा कहां से आया और किसे सप्लाई किया जाना था?
 - आरोपी के संपर्क में कौन-कौन लोग थे?
 - क्या इस गतिविधि का नेटवर्क धामनोद के बाहर भी फैला हुआ है?
 - स्थानीय पुलिस के मुखबिर तंत्र को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई?
 - पूर्व में आरोपी अथवा उसके मकान को लेकर कोई सूचना पुलिस तक पहुंची थी या नहीं?
 - थाना और सीआई सेल स्तर पर मादक पदार्थों के संबंध में कितनी सूचनाओं पर कार्रवाई की गई?
- इन तमाम बिंदुओं की निष्पक्ष समीक्षा होने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला स्थानीय पुलिस

की चूक, सूचना तंत्र की कमजोरी या किसी अन्य कारण से जुड़ा है।

नारकोटिक्स टीम की कार्रवाई ने बढ़ाई स्थानीय पुलिस की जवाबदेही

नारकोटिक्स सेल इंदौर की कार्रवाई में निरीक्षक अजय वास्कले, सजिन विजय मिश्रा, प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश राठौर, प्रधान आरक्षक राजरतन तायडे, आरक्षक रजनीश पाण्डेय, आरक्षक प्रदीप पाल तथा महिला आरक्षक वेल्का तिवारी का सराहनीय योगदान रहा। अब देखना यह होगा कि 12 लाख रुपए कीमत के 56 किलो 150 ग्राम गांजे की बरामदगी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थानीय पुलिस की निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा करते हैं या नहीं। नारकोटिक्स सेल ने कार्रवाई कर अपनी भूमिका निभा दी, लेकिन इस कार्रवाई ने धामनोद पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है- 'इतनी बड़ी मात्रा में नशे का माल थाना क्षेत्र में पहुंच गया, रखा गया और पुलिस को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी?' यही सवाल अब धामनोद थाना प्रभारी और सीआई सेल की कार्यप्रणाली की वास्तविक परीक्षा बन गया है।

देपालपुर में अवैध मदिरा के खिलाफ आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन

चांदेर से उषापुरा तक
आबकारी टीम की दबिश, तीन आरोपियों पर प्रकरण दर्ज
विश्वनाथ समाचार

देपालपुर। क्षेत्र में अवैध मदिरा के संग्रहण एवं विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग ने एक बार फिर प्रभावी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। कलेक्टर जिला इंदौर श्री शिवम वर्मा के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशानुसार कंट्रोलर कमलेश सोलंकी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में गत दिवस को वृत्त देपालपुर क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम चांदेर, अटवाड़ा, चटवाड़ा एवं उषापुरा स्थित यादव ढाबा सहित विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर अवैध मदिरा के संग्रहण एवं विक्रय की गतिविधियों की जांच की। कार्रवाई के दौरान सरदार पिता रामजी, दशरथ पिता भगीरथ एवं आनंद पिता देवकरण के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं



36(क) के तहत कुल तीन प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। देपालपुर वृत्त में इस कार्रवाई की महत्वपूर्ण कड़ी उप निरीक्षक राजेश वट्टी रहे। उनके नेतृत्व में टीम ने एक साथ कई क्षेत्रों में पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध मदिरा से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए मौके पर दबिश देना और सामने आए मामलों में नियमानुसार

प्रकरण दर्ज करना उनकी मैदानी सक्रियता एवं कार्यप्रणाली को दर्शाता है। राजेश वट्टी द्वारा टीम के साथ क्षेत्र में लगातार निगरानी एवं कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। विशेष रूप से ऐसे स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई करना, जहां अवैध मदिरा के संग्रहण या विक्रय की संभावना हो सकती है, विभागीय अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गत दिवस की कार्रवाई में



चांदेर, अटवाड़ा, चटवाड़ा और उषापुरा जैसे अलग-अलग स्थानों पर टीम की पहुंच यह दर्शाती है कि देपालपुर वृत्त में कार्रवाई को केवल एक स्थान तक सीमित न रखकर व्यापक क्षेत्र में निगरानी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई से अवैध मदिरा के संग्रहण एवं विक्रय में संलिप्त लोगों को स्पष्ट

संदेश दिया जा रहा है कि क्षेत्र में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। तीन अलग-अलग प्रकरणों का पंजीयन इसी अभियान का हिस्सा है। विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर देपालपुर वृत्त में की जा रही कार्रवाई का उद्देश्य अवैध मदिरा के कारोबार पर नियंत्रण करना और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना है। आने वाले दिनों में भी संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी एवं कार्रवाई जारी रहने की संभावना है। पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक राजेश वट्टी के साथ मुख्य आरक्षक रवींद्र कुमार बघेल, आरक्षक राशि सोलंकी एवं आरक्षक सावन सिसोदिया ने सक्रिय भूमिका निभाई। टीम के संयुक्त प्रयास से अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर तीन प्रकरण दर्ज किए गए। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि देपालपुर क्षेत्र में अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान को मैदानी स्तर पर लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के निर्देशन और उप निरीक्षक राजेश वट्टी के नेतृत्व में की जा रही कार्रवाई आने वाले समय में भी जारी रहने की उम्मीद है।

प्रदेशभर में 17 सितम्बर से एक माह तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान

इंदौर। मध्यप्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के अंतर्गत सभी 55 जिलों में नागरिकों की सेवा से जुड़े प्रकल्पों का आयोजन क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान के लिए जिलों का नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिये हैं। सेवा संकल्प अभियान 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2026 को हुई बैठक में भी दिशा-निर्देश दिए गए थे। सेवा संकल्प अभियान 2026 में अनेक गतिविधियां होंगी जिसमें आशीर्वाद का दीया जलाना, यानि हितग्राही परिवारों के घर पर दीप प्रज्वलन, सेवा चित्र राष्ट्रव्यापी ड्राईंग और भाषण प्रतियोगिता, सेवा स्मरण संगीतमय नाट्य प्रस्तुतियां, आंगन का मिलन यानि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान एवं बच्चों तथा माताओं की सक्रिय भागीदारी, कहानी बदलाव के तहत सरकार की योजनाओं से जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की सक्सेस स्टोरी, सेवा ज्योति यात्रा में गांव, जिला स्तर की जनभागीदारी यात्रा, विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ, वड़नगर (गुजरात) से वाराणसी यात्रा जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा, सेवा-मेरा योगदान के तहत 25 प्रमुख सेवा गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी होगी।

भाजपा की नाराजगी से जबरेश्वर सेना तक... अब सीधे अध्यक्ष की कुर्सी पर अनिल धाकड़ की नजर!

2022 की उपेक्षा का हिसाब 2027 में? ज़ भाजपा-कांग्रेस के बड़े चेहरों के सामने मैदान सजाने की तैयारी

◆ देपालपुर में त्रिकोणीय मुकाबले की आहट, चुनावी चौसर पर हर चाल पर जनता की नजर

विश्वनाथ समाचार

देपालपुर। नगरीय निकाय चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन देपालपुर की राजनीति में चुनावी गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस तक सीमित रहने के आसार नहीं हैं। राजनीतिक गलियारों में तीसरे मोर्चे की आहट साफ सुनाई देने लगी है और इस आहट के केंद्र में हैं पार्षद अनिल धाकड़। 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा से जुड़े रहे अनिल धाकड़ को राजनीतिक रूप से जिस तरह की अपेक्षा थी, वह पूरी नहीं हुई। अध्यक्ष की दौड़ में जगह नहीं मिली, उपाध्यक्ष की कुर्सी भी हाथ नहीं आई और प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल (पीआईसी) में भी स्थान नहीं मिला। यानी राजनीतिक गणित की किताब में उनके हिस्से का पन्ना खाली ही रह गया। यहीं से नाराजगी की कहानी शुरू हुई और धीरे-धीरे यह नाराजगी भाजपा से दूरी में बदलती चली गई। इसके बाद अनिल धाकड़ हिंदूवादी संगठन जबरेश्वर सेना से जुड़कर जनता के बीच सक्रिय हो गए।

कुर्सी नहीं मिली तो जनता के बीच जगह बनाने में जुट गए

पिछले तीन-चार वर्षों में

धाकड़ ने धार्मिक आयोजनों, भोजन भंडारों और सामाजिक गतिविधियों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। समर्थकों का दावा है कि वे लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे हैं। अब नवरात्रि के दौरान 16 अक्टूबर को देपालपुर की लोहार पट्टी में होने वाली बड़ी भजन संध्या को भी इसी राजनीतिक सक्रियता की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। सियासत में आयोजन सिर्फ आयोजन नहीं होते-उनमें भी संदेश छिपे होते हैं। मंच पर भजन चलता है, सामने श्रद्धालु बैठते हैं और राजनीतिक गलियारों में कैलकुलेटर चलने लगते हैं कि भीड़ कितनी थी, कौन आया था और किसने किससे हाथ मिलाया।

इस बार अनिल धाकड़ का 'मिशन अध्यक्ष' कितना गंभीर?

देपालपुर में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा यही है कि यदि इस बार नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के वोट से होता है तो अनिल धाकड़ पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर सकते हैं। यही वजह है कि उनकी गतिविधियों को अब केवल सामाजिक या धार्मिक

गतिविधियों के चरम से नहीं देखा जा रहा। राजनीतिक जानकार इसे आगामी चुनाव की जमीन तैयार करने की कवायद के रूप में भी देख रहे हैं। धाकड़ की तैयारी भी सामान्य चुनाव लड़ने वाली नहीं बताई जा रही। चर्चा है कि वे भाजपा के बड़े नेता और कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने अपनी टीम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रहे हैं। मतलब साफ है-इस बार मुकाबला 'टिकट किसे मिला' से आगे बढ़कर 'जनता किसे चुनती है' पर टिक सकता है।

2014 की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी

अनिल धाकड़ का भाजपा से नाराज होकर अलग राह पकड़ना देपालपुर की राजनीति में पहली बार नहीं देखा जा रहा। वर्ष 2014 में भी भाजपा ने नगर परिषद उपाध्यक्ष पद के लिए अनिल धाकड़ को नामांकित किया था। लेकिन तब वार्ड नंबर 9 से पार्षद नहीं अंजना दीनदयाल चौबे भाजपा से बागी होकर मैदान में उतरीं और उपाध्यक्ष का चुनाव जीत गईं। यानी देपालपुर की राजनीतिक डायरी में बगावत कोई नया अध्याय नहीं है। बस किरदार बदलते हैं, कुर्सियां बदलती हैं और चुनावी मौसम आते

ही पुराने पन्ने फिर खुल जाते हैं।

भाजपा-कांग्रेस के बीच तीसरा कोण बन गया तो?

देपालपुर में अब सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि अगर भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले अनिल धाकड़ अपनी टीम के साथ मजबूती से उतरते हैं तो चुनाव का पूरा समीकरण बदल सकता है। भाजपा के सामने चुनौती अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट रखने की होगी। कांग्रेस सत्ता-विरोधी माहौल या स्थानीय मुद्दों को कितना भुना पाती है, यह देखना होगा। वहीं धाकड़ के सामने चुनौती होगी कि धार्मिक-सामाजिक सक्रियता को वोट में कितनी मजबूती से बदला जा सकता है। यानी तीनों खेमों के पास अपनी-अपनी कहानी है और जनता के पास तीनों कहानियों का फैसला।

अब असली सवाल- कौन किसका खेल बिगाड़ेगा?

देपालपुर का चुनाव इस बार



सिर्फ जीत-हार का चुनाव नहीं दिख रहा। यहां वोट काटने, वोट जोड़ने और समीकरण बिगाड़ने की राजनीति भी महत्वपूर्ण होगी। अगर अनिल धाकड़ मजबूत तरीके से मैदान में उतरते हैं तो यह भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। कांग्रेस के लिए भी तीसरे कोण का उभरना आसान गणित नहीं होगा। और अगर भाजपा-कांग्रेस के बड़े चेहरे मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला चेहरे बनाम चेहरे और संगठन बनाम व्यक्तिगत पकड़ में बदल सकता है। कुल मिलाकर देपालपुर की चुनावी चौसर सजने

लगी है। अभी मोहरे पूरी तरह मैदान में नहीं आए हैं, लेकिन चालें चलनी शुरू हो गई हैं। भाजपा लड़े, कांग्रेस लड़े, अनिल धाकड़ अपनी टीम के साथ उतरीं या कोई नया निर्दलीय चेहरा अचानक ताल ठोक दे-इस बार देपालपुर की जनता को चुनाव में भरपूर राजनीतिक मनोरंजन मिलने के आसार हैं। क्योंकि देपालपुर की सियासत का मिजाज कुछ ऐसा है कि यहां चुनाव परिणाम आने तक हर नेता खुद को विजेता मानता है... और जनता चुपचाप तय करती रहती है कि असली अध्यक्ष कौन बनेगा।

सेन समाज ने कविता पाटीदार से की मुलाकात

धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मांग, शीघ्र कार्रवाई का मिला आश्वासन

विश्वनाथ समाचार

महू। सेन समाज महू तहसील के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार से मुलाकात कर समाज की धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटित किए जाने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि महू क्षेत्र में सेन समाज की सामाजिक गतिविधियों, बैठकों, विवाह समारोह सहित विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लंबे समय से एक स्थायी धर्मशाला की आवश्यकता महसूस की जा रही है। समाज की ओर से धर्मशाला निर्माण के लिए उपयुक्त शासकीय भूमि उपलब्ध कराने और आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधिमंडल की मांग पर कविता पाटीदार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए इसे गंभीरता से लिया तथा महू सेन समाज को धर्मशाला के लिए भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्र आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भारतीय सेन समाज के राष्ट्रीय महामंत्री गोकुल चौहान, मध्यप्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष बाबूलाल सेन, राजेंद्र हर्षवाल,



प्रकाश सेन, शिवराम सेन, मुकेश सेन, मोहनलाल भाटी, रमेश सोनौर, गौरव सेन एवं श्रीलाल सेन सहित समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समाज के प्रतिनिधियों ने कविता पाटीदार के समक्ष रखी मांग पर सकारात्मक आश्वासन मिलने पर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के

लिए भूमि उपलब्ध होने से महू में सेन समाज को सामाजिक, वैवाहिक एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए स्थायी सुविधा मिल सकेगी। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र आगे बढ़ेगी, जिससे महू में सेन समाज की बहुप्रतीक्षित धर्मशाला के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।

पदोन्नति के बाद ओम प्रकाश अहीर की नई पदस्थापना, अब संभालेंगे महिला सुरक्षा डीएसपी की जिम्मेदारी



विश्वनाथ समाचार

पीथमपुर। पीथमपुर सेक्टर नंबर-1 थाना प्रभारी ओम प्रकाश अहीर को डीएसपी पद पर पदोन्नति के बाद नई पदस्थापना मिल गई है।

गृह मंत्रालय द्वारा गुरुवार शाम जारी किए गए आदेश में पदोन्नत पुलिस अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की गई हैं। इसी आदेश के तहत ओम प्रकाश अहीर को उप पुलिस अधीक्षक, महिला सुरक्षा, धार के पद पर पदस्थ किया गया है। ओम प्रकाश अहीर वर्तमान में पीथमपुर सेक्टर नंबर-1 थाने के थाना प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पदोन्नति के बाद अब वे धार जिले में महिला सुरक्षा से जुड़ी पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद उनकी नई पदस्थापना प्रभावी होगी। पीथमपुर में थाना प्रभारी के रूप में उनके कार्यकाल के बाद अब नई जिम्मेदारी को

लेकर पुलिस महकमे में भी चर्चा है।

महिला सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी

उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा के रूप में अहीर के सामने महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम, मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा महिला सुरक्षा से जुड़े पुलिस तंत्र के समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। नई पदस्थापना के साथ वे धार जिले में पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे।

सम्पादकीय

ब्रिक्स शक्ति-संघर्ष का अखाड़ा नहीं, सहयोग का सेतु बने

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाला 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब विश्व व्यवस्था गहरे संक्रमण से गुजर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव, आतंकवाद, व्यापारिक टकराव, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा की चिंता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तेज होती चुनौती और वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर उठते प्रश्नों ने दुनिया के सामने अनेक अनुत्तरित सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका की व्यापार एवं रणनीतिक नीतियों से पैदा हो रहा दबाव भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ऐसे वातावरण में भारत की अध्यक्षता में होने वाला यह सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत ने अपनी अध्यक्षता का मूल मंत्र रखा है-लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के आधार पर भविष्य का निर्माण। ब्रिक्स अब 2006 में आरंभ हुई उस मूल अवधारणा से बहुत आगे निकल चुका है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सामने आए थे और बाद में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ। विस्तार के बाद यह 11 सदस्यीय समूह बन चुका है और इसका प्रभाव वैश्विक दक्षिण की राजनीति और अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ा है। वर्ष 2026 ब्रिक्स की स्थापना के दो दशक पूरे होने का वर्ष भी है। भारत के लिए यह अध्यक्षता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह ब्रिक्स को किसी पश्चिम-विरोधी या अमेरिका-विरोधी मंच के रूप में नहीं, बल्कि विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं की रचनात्मक, संतुलित और बहुपक्षीय आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है। ब्राजील में 2025 के ब्रिक्स सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने, बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार वैश्विक शासन, जलवायु वित्त, स्वास्थ्य, व्यापार और वित्तीय सहयोग जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण सहमति बनी थी। रियो घोषणा में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया था। साथ ही स्थानीय मुद्दाओं में वित्तीय लेन-देन, सीमा-पार भुगतान व्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ने की बात कही गई थी। भारत को 2026 की अध्यक्षता सौंपते हुए ब्राजील ने नई दिल्ली से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपेक्षा व्यक्त की थी। इस दृष्टि से दिल्ली सम्मेलन की पहली बड़ी कसौटी यही होगी कि ब्रिक्स घोषणाओं और वास्तविक उपलब्धियों के बीच की दूरी कितनी कम कर पाता है। भारत ने अध्यक्षता के दौरान 25 से अधिक शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग तथा सांस्कृतिक एवं जन-जन संपर्क-इन तीनों क्षेत्रों में व्यावहारिक परिणामों पर जोर दिया गया है। इसलिए अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि सम्मेलन के अंत में केवल लंबा संयुक्त घोषणापत्र सामने आता है या कुछ ऐसे ठोस फैसले भी होते हैं जिनका असर आने वाले वर्षों में दिखाई दे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। एआई ने चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वित्त और शासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं खोली हैं, लेकिन इसके साथ रोजगार, डेटा सुरक्षा, गलत सूचना, साइबर सुरक्षा और तकनीकी असमानता के खतरे भी बढ़े हैं। ब्राजील सम्मेलन में भी एआई के वैश्विक शासन को लेकर व्यापक चिंता व्यक्त की गई थी। भारत अब ब्रिक्स देशों के बीच एआई, उन्नत कंप्यूटिंग, क्वांटम तकनीक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में जोर दे रहा है। यदि ब्रिक्स तकनीक को कुछ शक्तिशाली देशों और कंपनियों के नियंत्रण से बाहर निकालकर विकासशील देशों की पहुंच तक ले जाने की प्रभावी व्यवस्था बना सके, तो यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बड़ी चुनौती आर्थिक है।

ईरान में बढ़ता तनाव दुनिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है

मध्य-पूर्व में तनाव की घटनाओं में स्पष्ट रूप से तेजी आई है। 8 अप्रैल को हुए दो सप्ताह के युद्धविराम के बाद संघर्ष बीच-बीच में चलता रहा था। लेकिन अब तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल का स्तर पार करने की ओर हैं, जो स्थिति में गंभीर गिरावट का संकेत है और जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिकी खुफिया आकलनों से संकेत मिलता है कि ईरान मध्य-पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ठिकानों पर हमला करने की अपनी क्षमता को लेकर आश्वस्त है और संघर्ष जारी रखने के इरादे पर कायम है। ईरान को चिंता है कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कारण उसकी अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। ईरान द्वारा अमेरिकी बेड़ों को निशाना बनाए जाने में रूस और चीन से मदद मिलने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि

उसके अपने लंबी दूरी के रडार अब तक नष्ट किए जा चुके हैं। अप्रैल के युद्धविराम के बाद जेडी वेंस और उनके ईरानी समकक्षों के बीच उच्चस्तरीय बातचीत हुई थी। लेकिन मतभेद दूर नहीं हो सके और बातचीत बेनतीजा रही। 13 अप्रैल को ट्रम्प ने ईरान की नाकेबंदी की घोषणा की, जिसके तहत ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात को निशाना बनाया जाना था। उन्होंने युद्धविराम को एकतरफा रूप से अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा भी दिया। हालांकि, जून के मध्य में दोनों पक्ष नए युद्धविराम की शर्तों पर सहमत हुए और युद्धविराम को 60 दिनों के लिए औपचारिक रूप से बढ़ाया गया। लेकिन 8 जुलाई तक औपचारिक युद्धविराम और समझौता ज्ञापन पूरी तरह विफल हो गया और दोनों पक्षों ने फिर से सीधे हमले शुरू कर दिए। ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे जहाजों को निशाना बनाया

और अमेरिका ने इसके जवाब में ईरान पर हमले किए। जुलाई के मध्य तक अमेरिका ने अपनी पूर्ण नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी। सितम्बर में ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला किया और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के तीन तेल टैंकर डुबो दिए। अब ईरान ने कहा है कि अगर उस पर दोबारा हमला किया गया तो वह खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर जवाब देगा। इससे फारस की खाड़ी में एनर्जी के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। इसका खामियाजा समूची वैश्विक अर्थव्यवस्था को उठाना होगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि उसकी नाकेबंदी और कठोर प्रतिबंध ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन अब तक ऐसा होने के कोई संकेत नहीं हैं। इसके बजाय हम तेहरान की प्रतिक्रिया को और तीखा होते देख रहे हैं। अमेरिका ने अब ऑपरेशन

इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ईरान के बचे हुए वित्तीय सहायों और आय के स्रोतों को काट देना है। नौसैनिक नाकेबंदी के साथ-साथ इस अभियान में उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और देशों पर प्रतिबंध और व्यापारिक दंड लगाने की धमकी दी गई है, जो तेहरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं। इन उपायों का निशाना डिजिटल एसेट्स, शिपिंग, विमानन, तकनीक और सोने तक ईरान की पहुंच है। भारत को अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वे ईरानियों की ऐसी व्यवस्थाएं बनाने में मदद न करें, जिनके जरिए वे राजस्व जुटा सकें। सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब है- ईरान से कोई व्यापार या वित्तीय लेन-देन नहीं। यह चेतावनी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पिछले महीने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियान से मुलाकात के बाद दी

गई। लेकिन अमेरिका ने चीन के साथ टकराव से बड़ी सावधानी से परहेज किया है, जबकि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार और उसका प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। 24 सितम्बर को शी जिनपिंग ट्रम्प के साथ शिखर बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे। ऐसे में अमेरिका चीन को नाराज नहीं करना चाहता। पिछले साल जब चीन ने रणनीतिक खनिजों और मैंगनेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, तब उसने दिखा दिया था कि वह अपने प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। अमेरिकी समझ चुके हैं कि चीन के मामले में निर्भरता एकतरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ है। अमेरिका को उम्मीद थी कि उसकी नाकेबंदी और प्रतिबंध ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय हम तेहरान की प्रतिक्रिया को और तीखा होते देख रहे हैं।

बिजनेस में सबसे जरूरी होते हैं भरोसा और कम्युनिकेशन

हर सीईओ को आखिरकार यह सीखना ही पड़ता है कि बोर्ड के साथ संबंध महज एक औपचारिकता नहीं है। यह कंपनी की रणनीतिक दिशा तय करता है। यही यह भी तय करता है कि लीडरशिप वास्तव में कितनी स्थिर है। विश्वास ही इसकी बुनियाद है। बोर्ड के साथ विश्वास अटूट होना चाहिए। इसका मतलब महज सहमति नहीं है। इसका मतलब है सम्मान और समय के साथ विकसित हुई वास्तविक, पारस्परिक समझ। जब यह विश्वास टूटता है- चाहे वह बोर्ड के भीतर हो या बोर्ड और सीईओ के बीच या मैनेजमेंट टीम के भीतर- तो नुकसान शायद ही कभी छोटा होता है। अकसर यह बेहद गंभीर होता है और लंबे समय तक बना रहता है। इसीलिए, संवाद का रास्ता खुला रखें। बोर्ड को उन जानकारीयों तक पहुंच होनी चाहिए, जो वास्तव में मायने रखती हैं। इसका मतलब रोजमर्रा के कामकाज पर नियंत्रण नहीं, बल्कि कारोबार में वास्तव में क्या हो रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी होना है। पारदर्शिता ही शुरुआत में विश्वास पैदा करती है। और यही बोर्डरूम में बेहतर फैसलों की ओर ले जाती है। यह फैसले लेने की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती। बेहतरीन सीईओ अपने बोर्ड को जानकारी देने के लिए तिमाही बैठक का इंतजार नहीं करते। वे संक्षिप्त और सारगर्भित अपडेट देने की एक नियमित व्यवस्था बनाते हैं, ताकि कोई भी बात अचानक सामने न आए। यह दोनों तरफ से काम करता है। बोर्ड को प्रतिक्रिया देने, सवाल

उठाने और अपना दृष्टिकोण रखने के लिए प्रोत्साहित करें। यही संवाद सीईओ को इस बात से वास्तविक रूप से जोड़े रखता है कि बोर्ड कंपनी को किस दिशा में ले जाना चाहता है। आपके बोर्ड को कुछ ऐसी बातें पता होती हैं, जो आपको नहीं पता। बहुत से सीईओ बोर्ड को एक ऐसे समूह के रूप में देखते हैं, जिसे मैनेज करना है, जिसे रिपोर्ट देना है और जिससे एक सुविधाजनक दूरी बनाए रखनी है। लेकिन यह एक गलती है। बोर्ड के सदस्यों के पास अलग-अलग उद्योगों और परिस्थितियों में काम करने का दशकों का अनुभव होता है, जिनमें से कई परिस्थितियों का सीईओ ने शायद कभी सीधे सामना न किया हो। इस अनुभव का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह रणनीतिक योजना बनाने में एक बड़ी पूंजी बन सकता है और वास्तविक संकट के समय तो और मूल्यवान साबित हो सकता है। यही कारण है कि बोर्ड सदस्यों की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लें। इसका इस्तेमाल रणनीति को और धार देने तथा उसके क्रियान्वयन को और मजबूत करने में करें। सबसे बेहतर गवर्नेंस ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली व्यवस्था नहीं होती। वह सहयोगात्मक होती है। औपचारिक बोर्ड बैठकें वास्तविक समझ विकसित करने की जगह नहीं होतीं। यह समझ उन बातचीत में बनती है, जो बैठक से पहले और बाद में होती हैं- जहां किसी निदेशक की वास्तविक चिंताएं और प्राथमिकताएं सामने आती हैं। समय

निकालकर यह समझने की कोशिश करें कि बोर्ड का हर सदस्य किन बातों को महत्व देता है और क्यों। इससे आपको उन टकरावों से बचने में मदद मिलेगी, जिनका आपको पहले से कोई अंदाजा नहीं था और जब बड़े फैसलों का समय आएगा, तब आपसी सहमति कायम करना भी कहीं आसान होगा। गवर्नेंस और उद्योग के रुझानों पर संयुक्त सत्र भी मददगार होते हैं। जो बोर्ड बदलते परिदृश्य से लगातार अपडेट रहता है, वह सिर्फ निगरानी करने वाला बोर्ड नहीं रहता, बल्कि वास्तविक मूल्य जोड़ता है। बोर्ड को कुशलता से संभालना यथास्थिति को बचाए रखने के बारे में नहीं है। यह इस रिश्ते को वास्तविक रणनीतिक बढ़त में बदलने के बारे में है। यही कारण है कि विश्वास कायम करें। पूरी पारदर्शिता के साथ संवाद करें। बोर्ड को महज एक चेकपॉइंट नहीं, बल्कि साझेदार के रूप में साथ लेकर चलें। इसे सही ढंग से किया जाए तो यह केवल गवर्नेंस की एक जिम्मेदारी नहीं रह जाती। यह कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सीईओ के पास मौजूद सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे कम इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों में से एक बन जाती है। बोर्ड को उन जानकारीयों तक पहुंच होनी चाहिए, जो वास्तव में मायने रखती हैं। इसका मतलब रोजमर्रा के कामकाज पर नियंत्रण नहीं, बल्कि कारोबार में वास्तव में क्या हो रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी होना है। पारदर्शिता ही शुरुआत में विश्वास पैदा करती है।

जमानत निरस्त होने के बाद फरार 20 साल की सजा वाला आरोपी सिद्दीक गिरफ्तार

पॉक्सो के गंभीर मामले में दोषी था आरोपी, जमानत पर रहते हुए फिर किया था अपराध; सादलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

विश्वनाथ समाचार

सादलपुर। गंभीर अपराध में 20 वर्ष के कारावास से दंडित होने के बाद जमानत पर बाहर आए और दोबारा अपराध करने वाले फरार आरोपी सिद्दीक पिता मुनीर खां, निवासी केसुर को सादलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की जमानत निरस्त होने के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए 7 सितंबर 2026 को उसे गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को जिला जेल धार भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार वर्ष 2019 में थाना सादलपुर में अपराध क्रमांक 332/2019 के तहत आरोपी

सिद्दीक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366-क, 376(2)(एन), 506 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एन)/6 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में माननीय न्यायालय ने 9 अप्रैल 2021 को आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।

जमानत पर रहते हुए फिर किया अपराध

पुलिस के मुताबिक उक्त प्रकरण में जमानत पर रहने के दौरान आरोपी ने वर्ष 2022 में पुनः अपराध क्रमांक 353/2022 घटित किया। इस मामले में उसके विरुद्ध



भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354(क)(1) (आई), 354 (क) (1)(आईआई) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11(मि1)/12 के तहत प्रकरण दर्ज

किया गया। दोबारा गंभीर अपराध में प्रकरण दर्ज होने के बाद सादलपुर पुलिस द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त करवाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की गई। माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर में

प्रचलित आपराधिक अपील क्रमांक 3172/2021 में आरोपी की जमानत निरस्त करवाई गई। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था।

लगातार तलाश के बाद पुलिस के हाथ लगा

जमानत निरस्त होने के बाद फरार आरोपी की तलाश में सादलपुर पुलिस लगातार जुटी हुई थी। पुलिस टीम ने सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए आरोपी की तलाश की और आखिरकार 7 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय धार के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल धार भेज दिया गया।

थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई की सराहना

पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (उत्तर) पारुल बेलापुरकर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बदनावर अरविंद सिंह तोमर के निर्देशन में की गई। आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण ठाकरे के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक राकेश सिंह मेड़ा एवं आरक्षक क्रमांक 1200 शैलेन्द्र विश्वकर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लंबे समय से फरार चल रहे गंभीर प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल पहुंचाने पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण ठाकरे और उनकी टीम की कार्रवाई की सराहना की जा रही है।

मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में छात्राओं से अभद्र व्यवहार, तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग

स्कूल की समस्या लेकर जिला पंचायत सीईओ से मिलने पहुंची थीं आठ छात्राएं, संकुल प्राचार्य भी थे साथ; छात्राओं ने कहा- ‘व्यवहार से हमें रोना आ गया’



विश्वनाथ समाचार

गौतमपुरा। नगर परिषद गौतमपुरा द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर के दौरान शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौतमपुरा की छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। छात्राएं विद्यालय से जुड़ी समस्या को लेकर इंदौर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) हिमांशु प्रजापति से मुलाकात करने शिविर में पहुंची थीं। छात्राओं के साथ विद्यालय के संकुल प्राचार्य पी.एन. देवले भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षाओं का दौर चल रहा होने के बावजूद विद्यालय की आठ छात्राएं अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर में पहुंची थीं।

छात्राएं जिला पंचायत सीईओ हिमांशु प्रजापति से मिलकर अपनी समस्या उनके समक्ष रखना चाहती थीं। आरोप है कि इसी दौरान तहसील टप्पा तहसीलदार कुलदीप सिंह ने छात्राओं के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और उन्हें वहां से विद्यालय वापस जाने के लिए कह दिया। छात्राओं के अनुसार तहसीलदार के व्यवहार से वे काफी आहत हुईं और उन्हें अपमानित महसूस हुआ और सभी बालिकाएं रोते हुवे आयोजन स्थल से बाहर चली गईं। घटना के दौरान मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने मामले की जानकारी शिविर के मंच तक पहुंचाई। इसके बाद मंच से घोषणा कर छात्राओं एलाउंस कर दोबारा शिविर में बुलाया गया। जिला पंचायत सीईओ हिमांशु प्रजापति ने छात्राओं की



समस्या सुनी और उसका शीघ्र निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया। छात्राओं ने बाद में अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि तहसीलदार के कथित व्यवहार से वे इतनी आहत हुईं कि उन्हें रोना आ गया और वे वहां से चली गईं। मामले की जानकारी जिला पंचायत सीईओ हिमांशु प्रजापति को भी दिए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, बताया जा रहा है कि घटना के समय हुए कथित व्यवहार की उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। ऐसे में अब पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद गौतमपुरा नगर में भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि जनसमस्याओं

के समाधान और आमजन को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित शिविर में छात्राओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार गंभीर विषय है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने तथा छात्राओं से माफी मांगने की मांग की है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों से आमजन, विशेषकर छात्राओं के प्रति संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा रहती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है।

शांति के टापू गौतमपुरा में डेढ़ माह में तीन हत्याएं

कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल, पुलिस की कार्यप्रणाली कटघरे में; सूचना-सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में

गौतमपुरा। इंदौर जिले में गौतमपुरा थाना क्षेत्र को लंबे समय से अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन बीते डेढ़ माह में तीन हत्या की वारदातों ने इस छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार सामने आ रही इन वारदातों ने न केवल क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ाई है, बल्कि पुलिस की अपराध रोकथाम और सूचना तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस गौतमपुरा को ‘शांति का टापू’ कहा जाता है, वहां इतनी कम अवधि में तीन हत्याएं आखिर कैसे हो गई? क्या पुलिस को इन घटनाओं की भनक पहले से नहीं लगी? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ कम हुआ है? और सबसे अहम-गौतमपुरा थाना पुलिस कानून-व्यवस्था को किस तरह संभाल रही है?



तीन हत्याओं ने बढ़ाई चिंता

डेढ़ माह के भीतर हुई तीन हत्याएं सामान्य अपराध की घटनाएं मानकर नजरअंदाज नहीं की जा सकतीं। लगातार सामने आ रही हिंसक वारदातें पुलिस के लिए गंभीर चेतावनी हैं। क्षेत्र में अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने, विवादों की समय रहते जानकारी जुटाने और संवेदनशील परिस्थितियों में प्रभावी पुलिसिंग करने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।

आसूचना-सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे सवाल

जानकारी के अनुसार आदित्य प्रताप सिंह, पंकेश सिंह, नरसिंह परमार और दीपक धाकड़ को आसूचना एवं सुरक्षा व्यवस्था से हटाया गया है। चर्चा यह भी है कि इन कर्मचारियों को अल्प समय के लिए तैनात किया जाता है और क्षेत्र में कोई बवाल या विवाद सामने आने के बाद उन्हें तत्काल हटा दिया जाता है। यदि ऐसा है तो सवाल यह है कि पुलिस का स्थानीय सूचना तंत्र आखिर किस आधार पर और कितनी स्थिरता के साथ काम कर रहा है? आसूचना तंत्र किसी भी थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम की पहली कड़ी माना जाता है। ऐसे में बार-बार कर्मचारियों को बदलना या अल्प अवधि में तैनाती करना कितना प्रभावी है, यह भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विचारणीय विषय है।

थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर निगाहें

लगातार तीन हत्याओं के बाद गौतमपुरा थाना प्रभारी अलका मेनिया की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि प्रत्येक हत्या के अपने अलग कारण और परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इतनी कम अवधि में तीन हत्याएं होना निश्चित तौर पर पुलिस की अपराध-नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा की मांग करता है। पुलिस के सामने अब चुनौती केवल आरोपियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भरोसा कायम करने की भी है कि क्षेत्र में अपराध होने से पहले उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचे और संभावित विवादों को समय रहते रोका जा सके। गौतमपुरा जैसे शांत माने जाने वाले थाना क्षेत्र में डेढ़ माह के भीतर तीन हत्याओं का होना गंभीर विषय है।

जनजाति मंत्री कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में जनजाति क्षेत्रों में रोजगार मेलो का आयोजन

इन्दौर। मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा वन वृत्त खंडवा के अंतर्गत स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 सितम्बर 2026 को चारखेड़ा तितली पार्क, हरसूद, जिला खंडवा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में लगभग 700 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिसमें से विभिन्न कंपनियों द्वारा लगभग 530 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग मंत्री श्री कुंवर विजय शाह उपस्थित थे। रोजगार मेले में सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों ने सहभागिता की। इन संस्थानों द्वारा युवाओं को असेंबली ऑपरेटर, स्पिनिंग ऑपरेटर, वीविंग ऑपरेटर, प्रोसेस ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, फिटर एवं इलेक्ट्रीशियन सहित विभिन्न पदों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 13 हजार रुपये तक का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत उन्हें 15 हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा। इसके साथ ही संबंधित कंपनियों द्वारा युवाओं को रियायती दरों पर छात्रावास एवं भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक, खंडवा वृत्त सुश्री बासुकनौजिया, वन मंडलाधिकारी खंडवा श्री राकेश डामोर, एसडीओ खंडवा एवं प्रशिक्षु आई.एफ.एस. श्री अजय गुप्ता, के सी.ई.ओ. श्री अनुज सक्सेना सहित वनमंडल खंडवा के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि खंडवा वन वृत्त द्वारा आयोजित यह दूसरा रोजगार मेला है। इससे पूर्व 2 अगस्त 2026 को उद्यमिता विकास केंद्र, आंवलिया, जिला खंडवा में प्रथम रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 138 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया था। उस कार्यक्रम में भी जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री श्री कुंवर विजय शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026

गौतमपुरा में आयोजित मुख्यमंत्री जन-विश्वास शिविर

गौतमपुरा में आयोजित मुख्यमंत्री जन-विश्वास शिविर में नागरिकों से किया संवाद और समस्याओं का मौके पर किया निराकरण

विश्वनाथ समाचार

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार शासन-प्रशासन को गांव की चौपाल तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 के तहत आज शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र देपालपुर के गौतमपुरा में जन-विश्वास शिविर आयोजित किया गया। मंडपम रिसोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और अनेक मामलों में मौके पर ही समाधान की कार्यवाई की। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भारत सिंह पटेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी, अनुविभागीय अधिकारी श्री चरणजीत सिंह हुड्डा, तहसीलदार गौतमपुरा श्री कुलदीप सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गौतमपुरा सुश्री मयूरी वर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती हर्षाली गगन बाहेली सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति ने अधिकारियों के साथ नगर परिषद द्वारा संचालित फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 20 केएलडी है। वर्तमान में यह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। उक्त ट्रीटमेंट प्लांट से जो खाद बनती है, उसका उपयोग बगीचे में किया जाता है।

अमृत पार्क में किया पौधारोपण

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति सहित अन्य



जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने अमृत पार्क में विभिन्न प्रजातियों के 50 से अधिक छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष एवं पार्षद व जिला स्तरीय दल एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा द्वारा पौधारोपण कर उद्यान का निरीक्षण किया। गौतमपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्ग पर मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देने वाली अनूठी पहल की गई। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के साथ स्वच्छता और सामुदायिक सुविधाओं का बेहतर होना ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्रमदान कर सफाई की।

अधिकारियों ने लिया मैदानी जायजा

जन-विश्वास शिविर केवल शिकायतों की सुनवाई तक सीमित नहीं रहा। अधिकारियों ने ग्राम का भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं, आवश्यकताओं और गांव में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। नागरिकों से सीधे संवाद कर यह भी समझा गया कि योजनाओं और लोक सेवाओं का लाभ उन्हें किस तरह मिल रहा है। शासकीय संस्थाओं और आधारभूत सुविधाओं का मैदानी

निरीक्षण किया तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का किया निरीक्षण

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रजापति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौतमपुरा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं टीकाकरण एवं अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती मरीजों से संवाद किया और हालचाल जाना। इस दौरान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. विभा नागर और डॉ. सुनील असाठी से स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार के लिए आने वाले मरीजों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने मंडी प्रांगण में स्थित आदर्श मार्केटिंग सोसायटी का निरीक्षण किया और हितग्राहियों को प्रदान किए जाने वाले राशन के बारे में जानकारी प्राप्त की।

स्कूली बच्चों के साथ किया संवाद और दिये करियर के मंत्र

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रजापति ने शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौतमपुरा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को स्कूल बैग, साहित्य और खेलकूद सामग्री का वितरण किया। उन्होंने



छात्रों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु करियर के मंत्र दिये। साथ ही बच्चों के साथ सामूहिक चित्र खिंचवाये। निरीक्षण के दौरान श्री प्रजापति ने विद्यालय के प्रभारी एवं शिक्षकों से विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में चर्चा की। इस मौके पर परियोजना अधिकारी डॉ. अनीता जोशी सहित अन्य अधिकारियों ने आंगनवाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया।

स्वास्थ्य शिविर भी लगा स्वास्थ्य जांच के साथ आधार अपडेशन की सुविधा

इस अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जो नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहा। शिविर में 230 मरीजों की ओपीडी, 75 आयुष्मान कार्ड, 117 आभा आईडी एवं 04 दिव्यांग कार्ड बनाए गए। साथ ही आयुष चिकित्सा, मेडिकल बोर्ड सहित विभिन्न जनहितकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस अवसर पर टीबी मरीजों को निक्षय मित्र के माध्यम से फूड बास्केट तथा कुछ रोगियों को सेल्फ केयर किट वितरित की गई। ओपीडी में आए मरीजों को फल भी वितरित किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनविश्वास

के तहत आज सुबह कलेक्टर कार्यालय से संबंधित अधिकारियों का दल बस में सवार होकर गौतमपुरा में आयोजित जन-विश्वास शिविर में सहभागिता करने के लिए जनता के बीच पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

उद्यमियों ने सुनाई सफलता की कहानी

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थी को विभिन्न योजनाओं में लाभ प्रदान किया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत श्री अंकित को 2.50 लाख रुपये का लोन प्रदान किया गया। श्री अंकित ने बताया कि इस योजना से प्राप्त ऋण से गौतमपुरा में कपड़े का व्यवसाय प्रारंभ किया। इससे मेरी आमदनी बढ़ी है। साथ ही उद्यम क्रांति योजना के तहत श्री मोहम्मद जुनेद को खाद एवं बीज की दुकान के लिए ऋण दिया गया। श्री जुनेद ने बताया कि इस व्यवसाय से मेरी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जन-विश्वास अभियान में आयोजित शिविर में नागरिकों की विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों का संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निराकरण किया गया। इस अवसर पर रूस्स्थ प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की जानकारी दी गई। शिविर में विभिन्न लाभार्थियों को भी लाभान्वित करते हुए पात्रता पर्ची, संबल योजना, कर्मकार मंडल, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कल्याणी पेंशन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। शिविर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ भी नागरिकों को उपलब्ध कराया गया।

एनआरएलएम की दीदीयों द्वारा अपने उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई

अधिकारी एक ही बस से जन-विश्वास शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान

रक्षाबंधन पर 10 ग्राम कम मिठाई देने वाले फर्म पर विभाग ने 5 हजार रुपए का लगाया था जुर्माना

इंदौर। संभागयुक्त श्री भास्कर लाक्षाकार ने आज नापतौल विभाग के कार्यों और अब तक की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की। विभाग द्वारा बताया गया कि अप्रैल माह से अब तक 175 प्रकरण बनाए गए हैं। इसमें रक्षाबंधन एवं अन्य त्योहारों के दौरान विभाग द्वारा तत्परता से कार्य किया गया। विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा से कम गैस सप्लाई करने पर कार्यवाही की गई। ऑनलाइन शॉपिंग व्यापार के बिग बास्केट द्वारा एमआरपी से अधिक चार्ज करने पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह रक्षाबंधन के दौरान



अधिकांश प्रकरण सामने आए हैं। इसमें 10 ग्राम मिठाई कम देने पर फर्म पर 5 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह ऑटोमोबाइल पार्ट्स

पर अधिक चार्ज करने के मामले में 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। बैठक में उपनियंत्रक श्री संजय पाटणकर, नापतौल निरीक्षक श्री

खेमराज चौधरी, श्री कपिल कदम सहित श्री के. एस. ठाकुर, श्री शरद शर्मा एवं एम.एम. राजपूत उपस्थित रहें। बैठक में संभागयुक्त श्री लाक्षाकार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी सिंहस्थ के महेनजर एक व्यवस्थित विभागीय रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के पूरे विस्तार को समझें और उसके उपरांत ही योजना तैयार करें। इसके अलावा उन्होंने शॉपिंग मॉल्स में खाद्य पदार्थों के बिकने वाली वस्तुओं की पैकिंग का सत्यापन प्राथमिकता के साथ किया जाए।

शास्त्री ब्रिज के पुनर्निर्माण की बड़ी पहल, पहले बनेगा नया समानांतर ब्रिज- सांसद शंकर लालवानी

इंदौर। शहर के प्रमुख शास्त्री ब्रिज के पुनर्निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए पुराने शास्त्री ब्रिज को तोड़ने से पहले उसके समानांतर नया ब्रिज बनाया जाएगा। इससे निर्माण के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी और नागरिकों को आवागमन में परेशानी नहीं होगी। सांसद शंकर लालवानी की लगातार पहल और प्रयासों के परिणामस्वरूप शास्त्री ब्रिज के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को गति मिली है। सांसद लालवानी द्वारा इंदौर की प्रमुख अधोसंरचनाओं को मजबूत करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर लगातार संबंधित विभागों के साथ चर्चा की जा रही है। शास्त्री ब्रिज का निर्माण कार्य दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में वर्तमान ब्रिज के समानांतर नया ब्रिज बनाया जाएगा। योजना के अनुसार नए समानांतर ब्रिज को सिंहस्थ-2028 से पहले यातायात के लिए उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नया ब्रिज शुरू होने के बाद पुराने शास्त्री ब्रिज को तोड़ा जाएगा तथा दूसरे चरण में शेष निर्माण कार्य किया जाएगा। नए ब्रिज की ऊंचाई वर्तमान शास्त्री ब्रिज की तुलना में अधिक रखी जाएगी, जिससे भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर और आधुनिक सुविधा उपलब्ध हो सके।

आंखों में रोशनी नहीं, फिर भी सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्य में जला रहे ज्ञान का दीप

ब्रेल लिपि से शिक्षा हासिल कर शिक्षक बने राजेश जायसवाल, हौसले और संघर्ष से लिखी सफलता की कहानी

विश्वनाथ समाचार

देपालपुर। कुछ लोग आंखों से दुनिया देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने हौसले, ज्ञान और कर्म से दूसरों की दुनिया रोशन करते हैं। देपालपुर विकासखंड के शिक्षा विभाग में कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षक राजेश जायसवाल ऐसी ही प्रेरणादायी मिसाल हैं। आंखों की रोशनी उनका साथ नहीं देती, लेकिन उनके भीतर ज्ञान का ऐसा उजाला है, जिसकी रोशनी आज विद्यार्थियों के भविष्य तक पहुंच रही है। राजेश जायसवाल ने जीवन की चुनौतियों को अपनी राह का रोड़ा बनने देने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाया। शिक्षा हासिल करने की राह में जब

सामान्य परिस्थितियां उनके लिए सहज नहीं थीं, तब उन्होंने ब्रेल लिपि को अपना माध्यम बनाया और निरंतर अध्ययन करते हुए अपने सपनों को आकार दिया। संघर्ष, मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर उन्होंने सरकारी शिक्षक बनने का मुकाम हासिल किया।

दृष्टिबाधिता को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया

राजेश का जीवन इस बात का उदाहरण है कि परिस्थितियां इंसान की मंजिल तय नहीं करतीं, बल्कि उसकी इच्छाशक्ति और प्रयास उसकी दिशा तय करते हैं। पढ़ाई के दौरान अनेक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं माना। ब्रेल लिपि के सहारे शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने अपने ज्ञान को मजबूत किया और सरकारी सेवा तक पहुंचे। आज वही



व्यक्ति, जिसने कभी खुद शिक्षा पाने के लिए संघर्ष किया था, अब विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी दे रहा है। उनकी कक्षा में केवल किताबों का ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि जीवन की एक ऐसी सीख भी मिलती है, जो शायद किसी पाठ्यपुस्तक में नहीं लिखी होती—मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, हौसला उनसे बड़ा होना चाहिए।

नौकरी नहीं, विद्यार्थियों का भविष्य संवारना है मिशन

राजेश जायसवाल के लिए शिक्षक होना केवल सरकारी नौकरी या रोजमर्रा की जिम्मेदारी नहीं है। वे इसे विद्यार्थियों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ ही वे उन्हें जीवन में आगे बढ़ने, आत्मविश्वास बनाए रखने और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि इंसान की पहचान उसकी शारीरिक क्षमता से नहीं, बल्कि उसकी सोच, मेहनत और संकल्प से होती है। शायद यही कारण है कि उनका जीवन स्वयं उनके विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणादायी किताब बन गया है।

जीवनसाथी का साथ बना संघर्ष की ताकत

राजेश जायसवाल की कहानी

में उनके जीवनसाथी के सहयोग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी पत्नी भी दिव्यांग हैं, लेकिन दोनों ने अपनी परिस्थितियों को कभी अपने सपनों और जीवन की राह में बाधा नहीं बनने दिया। रोजमर्रा के जीवन से लेकर स्कूल आने-जाने तक, उनकी पत्नी राजेश का सहयोग करती हैं। दोनों के बीच का विश्वास, आपसी समझ और साथ इस बात की खूबसूरत मिसाल है कि जब जीवन की राह में दो लोग एक-दूसरे का हाथ थामकर चलते हैं, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।

आंखों से दुनिया नहीं देख पाते, लेकिन सपनों की राह दिखा रहे

राजेश जायसवाल की कहानी महज एक दृष्टिबाधित शिक्षक की कहानी नहीं है। यह उस जज्बे की कहानी है, जिसने अभाव को अवसर में और

चुनौती को उपलब्धि में बदल दिया। वे अपनी आंखों से शायद दुनिया को नहीं देख पाते, लेकिन अपने ज्ञान और अनुभव से विद्यार्थियों के सपनों को दिशा दे रहे हैं। जिन बच्चों को वे पढ़ाते हैं, उनके भविष्य में सफलता की संभावनाओं का उजाला देखना ही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। राजेश जायसवाल यह संदेश देते हैं कि रोशनी केवल आंखों में नहीं होती। असली रोशनी उस सोच में होती है, जो अंधेरे में भी रास्ता तलाश लेती है। उन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपनी सीमा नहीं बनने दिया और साबित किया कि यदि इरादे मजबूत हों तो जिंदगी की कोई भी कमी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उनकी आंखों में भले ही रोशनी नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान का दीप आज उन सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्य में उजाला कर रहा है, जिन्हें वे शिक्षा और सफलता की राह दिखा रहे हैं।

स्वच्छता कर बढ़ोतरी पर देपालपुर में गरमाई सियासत, आम आदमी की जेब पर बढ़ा बोझ

महंगाई के बीच नगर परिषद के बढ़े कर ने बढ़ाई लोगों की चिंता, अगस्त से लागू हुई नई दरें; चुनावी साल में मुद्दा बनने के आसार

विश्वनाथ समाचार

देपालपुर। गत दिवस आयोजित नेशनल लोक अदालत के बाद नगर परिषद देपालपुर द्वारा बढ़ाए गए स्वच्छता कर को लेकर नगर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम नागरिकों के सामने अब नगर परिषद के बढ़े हुए स्वच्छता कर ने एक और आर्थिक बोझ खड़ा कर दिया है। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर बिजली, पानी और अन्य खर्चों तक लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच नगर परिषद के अतिरिक्त कर ने घरेलू बजट को और प्रभावित किया है। नगर परिषद द्वारा स्वच्छता कर में की गई वृद्धि को लेकर बाकायदा विज्ञप्ति जारी करने, मुनादी कराने और परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित किए जाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। नई कर व्यवस्था अगस्त माह से लागू होने की जानकारी सामने आई है। इसके तहत कई श्रेणियों में स्वच्छता कर की राशि पूर्व की तुलना में काफी बढ़ गई है। नई व्यवस्था के अनुसार मकान पर 720 रुपये, मकान एवं दुकान पर 2160 रुपये तथा व्यवसायिक दुकान पर 1440 रुपये स्वच्छता कर निर्धारित किए जाने की बात सामने आ रही है। कुछ श्रेणियों में कर की राशि पूर्व की तुलना में लगभग दोगुनी होने से नागरिकों में नाराजगी और असमंजस की स्थिति भी दिखाई दे रही है। जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब महंगाई लगातार आम आदमी की



आय और खर्च के बीच अंतर बढ़ा रही है, तब स्थानीय निकाय द्वारा करों में वृद्धि का फैसला कितना उचित है? स्वच्छता व्यवस्था नगर परिषद की मूलभूत जिम्मेदारियों में शामिल है, लेकिन नागरिक यह भी जानना चाहते हैं कि बढ़े हुए कर के अनुपात में उन्हें स्वच्छता सेवाओं में कितना अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

चुनाव से पहले बढ़ा कर, राजनीतिक असर पर निगाह

नगर निकाय चुनाव में अब ज्यादा समय शेष नहीं है। ऐसे में स्वच्छता कर में हुई वृद्धि आने वाले समय में राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। परिषद के इस निर्णय का राजनीतिक लाभ या नुकसान किसे होगा, इसका फैसला आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में जनता के रुख से ही स्पष्ट होगा। वहीं, विपक्षी कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को तत्काल प्रभाव से जनता के बीच उठाने के बजाय आगामी नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की संभावनाओं को लेकर भी चर्चाएं हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस विषय पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। स्वच्छता कर की मौजूदा वृद्धि को लेकर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष ठाकुर के कार्यकाल की भी नगर में चर्चा हो रही है। उनके कार्यकाल के दौरान संपत्तिकर, जलकर और बाजार बैठक कर सहित अन्य करों को यथास्थिति रखने की नीति अपनाए जाने की बात कही जा रही है।

बताया जाता है कि जलकर अधिक होने के कारण उसमें भी परिषद की बैठक के माध्यम से कमी किए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी पुराने उदाहरण को सामने रखकर अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जब पूर्व में करों का बोझ कम करने की दिशा में निर्णय लिए गए थे, तो वर्तमान समय में कर बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

जनता पूछ रही—कर बढ़ा तो सुविधा कितनी बढ़ी?

देपालपुर की गलियों और बाजारों में अब असली चर्चा सिर्फ कर की राशि को लेकर नहीं, बल्कि कर के बदले मिलने वाली सुविधा को लेकर है। नागरिकों का सीधा सवाल है—यदि स्वच्छता कर बढ़ाया गया है तो क्या सफाई व्यवस्था भी उसी अनुपात में बेहतर होगी? क्या नियमित कचरा संग्रहण, सफाई व्यवस्था और अन्य स्वच्छता सेवाओं में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा? आम आदमी के लिए कुछ सौ रुपये भी मायने रखते हैं। महीने-दर-महीने बढ़ते खर्चों के बीच सालाना कर में हुई वृद्धि भले ही सरकारी आंकड़ों में छोटी दिखाई दे, लेकिन सीमित आय वाले परिवार के बजट में इसका असर साफ महसूस होता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर परिषद बढ़े हुए स्वच्छता कर के पीछे अपने निर्णय को जनता के सामने किस तरह उचित ठहराती है और विपक्ष इस मुद्दे को तत्काल जनहित के सवाल के रूप में उठाता है या फिर चुनावी मुद्दा बनने तक इंतजार करता है। फिलहाल देपालपुर में स्वच्छता कर की बढ़ोतरी ने जनचर्चा के साथ-साथ स्थानीय राजनीति का तापमान भी बढ़ा दिया है।

स्कूल की बाउंड्री पर कब्जा, जिम्मेदार अधिकारियों की कार्रवाई का इंतजार

पटवारी की रिपोर्ट और प्राचार्य के पत्राचार के बावजूद मामला ठंडे बस्ते में, सरकारी स्कूल की भूमि की सुरक्षा पर उठे सवाल विश्वनाथ समाचार

देपालपुर। शासकीय संपत्ति और शिक्षा संस्थानों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने के प्रशासनिक दावों के बीच गोकलपुर स्थित शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल की बाउंड्री पर कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। गंभीर बात यह है कि इस संबंध में पटवारी हेमराज केलवा द्वारा नायब तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार स्कूल की बाउंड्री से संबंधित कथित कब्जे की स्थिति को लेकर पटवारी हेमराज केलवा ने मौका स्थिति का संज्ञान लेते हुए नायब तहसीलदार को रिपोर्ट दी थी। इसके बावजूद लंबे समय से मामला कार्रवाई की प्रतीक्षा में है। वहीं, शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य द्वारा भी संबंधित अधिकारी को पत्राचार कर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की जा चुकी है। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं?

मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राजस्व विभाग के पटवारी स्तर से रिपोर्ट



प्रस्तुत की जा चुकी है और स्कूल के प्राचार्य द्वारा भी अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है, तो आखिर कार्रवाई किस स्तर पर अटकी हुई है? सरकारी स्कूल की भूमि और उसकी बाउंड्री की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में कथित अतिक्रमण को लेकर समय रहते कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि यदि शासकीय शिक्षण संस्थान की भूमि पर कब्जे की स्थिति बनती है और शिकायत एवं रिपोर्ट के बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में ऐसे मामलों को बढ़ावा मिलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

अधिकारी बोले—‘मेरे संज्ञान में नहीं है, दिखवा लेता हूं’

मामले को लेकर जब नायब

तहसीलदार देपालपुर आनंद जायसवाल से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा— ‘मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं दिखवा लेता हूं।’ अब देखना यह होगा कि अधिकारी के संज्ञान में मामला आने के बाद राजस्व विभाग द्वारा मौके की जांच कर कथित अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाती है या नहीं और यदि कब्जा शासकीय भूमि पर पाया जाता है तो जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कब तक होती है।

जनता का सवाल

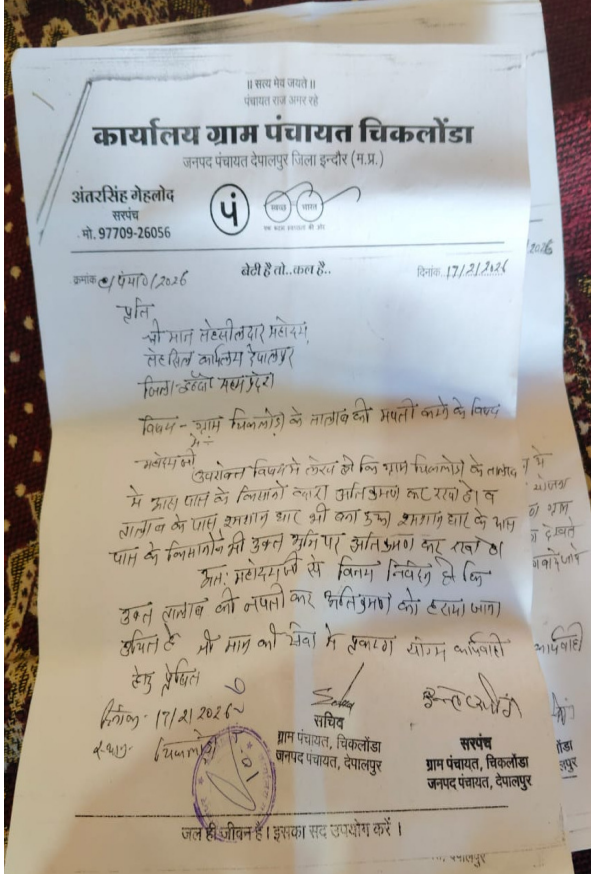
जब पटवारी की रिपोर्ट और स्कूल प्राचार्य का पत्राचार मौजूद है, तो कार्रवाई के लिए और कितने पत्र और रिपोर्ट की जरूरत है? सरकारी स्कूल की भूमि की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कब गंभीर कदम उठाएगा—यह सवाल अब जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जा रहा है।

तालाब की जमीन निजी मद में कैसे पहुंची? नामांतरण के बाद खरीद-फरोख्त, वर्षों से जांच के इंतजार में मामला



चिकलौड़ा पंचायत के तालाब से जुड़ी भूमि को लेकर गंभीर सवाल, 2023 में पटवारी रिपोर्ट के आधार पर हुआ नामांतरण; जनविश्वास शिविर में मामला सामने आने के बाद जांच के निर्देश, फिर भी कार्रवाई के बजाय अपील का रास्ता दिखाने पर उठे सवाल

देपालपुर। ग्राम पंचायत चिकलौड़ा के पंचायत तालाब से जुड़ी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि पंचायत के तालाब की शासकीय भूमि का सर्वे नंबर राजस्व रिकॉर्ड में निजी मद में दर्ज हो गया और इसके बाद भूमि की खरीद-फरोख्त तक हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भूमि वास्तव में शासकीय तालाब की थी तो वह निजी मद में कैसे दर्ज हुई और उस प्रविष्टि के आधार पर आगे नामांतरण की प्रक्रिया कैसे पूरी हो गई? मामले से जुड़े वर्ष 2023 के राजस्व न्यायालय के आदेश में राजस्व ग्राम चिकलौड़ा, तहसील देपालपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 22/3, रकबा 1.856 हेक्टेयर में से उत्तर दिशा की ओर स्थित 0.928 हेक्टेयर भूमि के विक्रय का उल्लेख है। आदेश में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 179092023ए12014456 दिनांक 20 जून 2023 के आधार पर नामांतरण का प्रकरण दर्ज होना बताया गया है। आवेदक की ओर से विक्रय पत्र सहित खसरा, किस्तबंदी खतौनी और बी-1 की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई थीं। इस पूरे मामले की अहम कड़ी तत्कालीन पटवारी पूनम मारू की रिपोर्ट है। नामांतरण प्रकरण में मौजा पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई थी। पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में सर्वे क्रमांक 22/3 की 1.856



हेक्टेयर भूमि को संबंधित विक्रेताओं के नाम निजी मद में दर्ज बताया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त भूमि में से उत्तर दिशा की ओर की 0.928 हेक्टेयर भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रेता को विक्रय की गई है। यहीं से मामले की गंभीरता बढ़ जाती है। शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित सर्वे नंबर देपालपुर जनपद की ग्राम पंचायत चिकलौड़ा के पंचायत तालाब की भूमि है और पूर्व में यह भूमि शासकीय मद से संबंधित थी। यदि यह तथ्य मूल राजस्व एवं बंदोबस्त अभिलेखों से प्रमाणित होता है, तो फिर यह जांच का विषय बन जाता है कि शासकीय तालाब की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में निजी मद में किस प्रक्रिया और किस आधार पर दर्ज हुई। केवल 2023 की पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर आगे बढ़ने के बजाय उस प्रविष्टि की मूल कड़ी तलाशना अब प्रशासन के लिए जरूरी हो गया है। प्रकरण के साथ संलग्न पुराने खसरा बंदोबस्त/बंदोबस्त अभिलेख भी

इस मामले में खास महत्व रखते हैं। यही अभिलेख यह स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं कि संबंधित भूमि की पुरानी राजस्व स्थिति क्या थी और वर्तमान रिकॉर्ड तक पहुंचते-पहुंचते उसमें क्या परिवर्तन हुआ। इसलिए जांच यदि वास्तव में निष्पक्ष तरीके से होती है तो वर्ष 2023 के नामांतरण आदेश से पहले की पूरी राजस्व रिकॉर्ड-चेन की पड़ताल करना आवश्यक होगा। वर्ष 2023 में तत्कालीन राजस्व अधिकारी के समक्ष नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत हुआ। प्रकरण दर्ज किया गया, विज्ञप्ति प्रकाशित हुई और मियाद अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने का उल्लेख आदेश में है। इसके बाद पटवारी प्रतिवेदन और प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करते हुए नामांतरण स्वीकार किया गया। आदेश में विक्रित 0.928 हेक्टेयर भूमि के संबंध में विक्रेताओं के स्थान पर क्रेता का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने तथा नामांतरण के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने

के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस प्रक्रिया के दौरान जमीन की वास्तविक स्थिति और तालाब से उसके संबंध की पर्याप्त जांच नहीं हुई। हालांकि यह आरोप जांच का विषय है, लेकिन दस्तावेजों के सामने आने के बाद अब यह सवाल जरूर उठता है कि क्या नामांतरण से पहले मूल बंदोबस्त रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया गया था? यदि पंचायत तालाब के रूप में भूमि का उपयोग करती रही है और पंचायत ने बाद में भी तालाब के सीमांकन के लिए कई बार पत्राचार किया है, तो उन पत्रों और संबंधित पंचायत रिकॉर्ड को भी जांच में शामिल करना जरूरी है। नामांतरण के बाद शिकायत सामने आने पर मामला नायब तहसीलदार बोर्ड देपालपुर के समक्ष पहुंचा और शिकायतकर्ता के अनुसार कई वर्षों से लंबित है। इस दौरान करीब चार से पांच तहसीलदार बदल चुके हैं, लेकिन प्रकरण में प्रभावी सुनवाई और अंतिम निर्णय नहीं हो सका। सवाल यह है कि जिस मामले में शासकीय तालाब की भूमि के निजी मद में दर्ज होने और उसके बाद खरीद-फरोख्त के आरोप लगाए जा रहे हैं, वह मामला वर्षों तक लंबित क्यों रहा? मामला मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर में जिला पंचायत सीईओ हिमांशु प्रजापति के समक्ष उठाए जाने के बाद और गंभीर हो गया। शिकायतकर्ता के अनुसार सीईओ ने मामले की जांच के लिए एसडीएम चरणजीत सिंह हुड्डा को निर्देश दिए। इसके बाद उम्मीद थी कि मूल रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, मौके पर तालाब का सीमांकन होगा और यह स्पष्ट किया जाएगा कि राजस्व रिकॉर्ड और जमीन की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर है या नहीं। लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार एसडीएम की ओर से उन्हें यह कहा गया कि 'आप अपील कर दो, मैं इसे निरस्त कर दूंगा।' यदि यह बात आधिकारिक रिकॉर्ड से पुष्ट होती है, तो यह भी जांच का विषय है कि जब जिला स्तर पर मामला जांच के लिए सामने आ चुका है और भूमि की प्रकृति

को लेकर गंभीर प्रश्न मौजूद हैं, तब केवल अपील की प्रक्रिया की ओर इशारा करना पर्याप्त है या नहीं। शिकायतकर्ता का मूल सवाल नामांतरण आदेश के खिलाफ अपील भर नहीं, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया की जांच है जिसके चलते कथित तौर पर तालाब की भूमि निजी मद में दर्ज हुई और फिर उसका विक्रय हुआ। ग्राम पंचायत चिकलौड़ा द्वारा तालाब के सीमांकन के लिए किए गए पत्राचार भी अब इस मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज बन सकते हैं। यदि पंचायत ने समय-समय पर प्रशासन से तालाब का सीमांकन कराने की मांग की है, तो उन पत्रों पर हुई कार्रवाई और मौके की वास्तविक स्थिति को रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है। तालाब कहां है, उसकी वास्तविक सीमा कितनी है, संबंधित सर्वे नंबर का कितना हिस्सा तालाब में आता है और राजस्व रिकॉर्ड में उसकी मद क्या है—इन सवालों का जवाब मौके के सीमांकन और मूल अभिलेखों के मिलान से ही मिल सकता है। मामले में अब जिला प्रशासन के सामने सबसे अहम चुनौती यही है कि जांच को केवल फाइलों की आवाजाही तक सीमित न रखा जाए। मूल मिसल बंदोबस्त से लेकर वर्तमान खसरा, बी-1, नामांतरण प्रकरण, पटवारी रिपोर्ट, विक्रय पत्र और पंचायत के सीमांकन संबंधी पत्राचार को एक साथ रखकर जांच की जाए। यदि रिकॉर्ड में कोई बदलाव हुआ है तो उसका आदेश और आधार सामने आए और यदि जमीन वास्तव में शासकीय तालाब की पाई जाती है तो उसके संरक्षण तथा राजस्व रिकॉर्ड को नियमानुसार दुरुस्त

करने की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाए। यह मामला फिलहाल आरोप और अभिलेखीय स्थिति के बीच जांच का विषय है, इसलिए किसी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सर्वे नंबर 22/3 की जमीन की वास्तविक स्थिति अब सार्वजनिक जांच के दायरे में आ चुकी है। 2023 का नामांतरण आदेश मौजूद है, पटवारी रिपोर्ट में जमीन को निजी मद में बताया गया है और दूसरी ओर ग्राम पंचायत की ओर से इसे तालाब की भूमि बताए जाने तथा सीमांकन की मांग किए जाने की बात सामने आ रही है। इन विरोधाभासी दावों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है—सच किस रिकॉर्ड में है? जिला प्रशासन यदि इस मामले में पारदर्शिता के साथ मूल बंदोबस्त रिकॉर्ड की जांच, मौके का सीमांकन और पूरी नामांतरण फाइल का परीक्षण करा दे तो स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सकती है। यदि शिकायत निराधार है तो प्रशासन को रिकॉर्ड के आधार पर उसे स्पष्ट करना चाहिए और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो नियमानुसार जिम्मेदारी तय करने के साथ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। चिकलौड़ा के तालाब की जमीन का मामला अब सिर्फ एक नामांतरण की फाइल नहीं है। यह राजस्व रिकॉर्ड की विश्वसनीयता, पंचायत की सार्वजनिक संपत्ति और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा सवाल बन चुका है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस सवाल का जवाब फाइलों की अगली तारीख से देता है या मूल रिकॉर्ड और जमीन पर उतरकर जांच से।

मौका मुआयना के बाद भी कार्रवाई ठंडी

21 फरवरी 2026 को तत्कालीन तहसीलदार धर्मेन्द्र चौकसे एवं पटवारी राहुल शर्मा ने चिकलौड़ा तालाब पहुंचकर जांच व मौका मुआयना किया था। मौके पर तालाब की भूमि पर अतिक्रमण तथा मुक्तिधाम की भूमि पर कब्जे जैसी स्थिति सामने आने की बात सामने आई। इसके बावजूद मौका निरीक्षण के बाद आज दिनांक तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। आखिर जांच के बाद तैयार रिपोर्ट किस स्तर पर लंबित है और कार्रवाई किसके इंतजार में रुकी हुई ?